

**जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) पुरस्कारों के दूसरे संस्करण में कौशल विकास में अनुकरणीय योजना के लिए 30 जिलों को सम्मानित किया गया**

- जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) पुरस्कारों में 467 जिलों ने भाग लिया।
- तीन जिले क्रमशः राजकोट, कछार और सतारा शीर्ष पर रहे।



**नई दिल्ली, 9 जून, 2022:** जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार (डीएसडीपी) का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बड़े उत्साह और धूमधाम से आयोजित किया गया, जहां शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास के क्षेत्र में उनके सर्वोत्तम अभिनव कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। भाग लेने वाले सभी जिलों में क्रमशः गुजरात का राजकोट, असम का कछार और महाराष्ट्र का सतारा जिला शीर्ष तीन में थे।

**30 राज्यों के जिला कलेक्टरों, जिलाधिकारियों और अन्य प्रतिनिधियों ने पुरस्कार समारोह में भाग लिया और अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया तथा अपने जिलों में जमीनी स्तर पर किए गए कौशल विकास कार्यों को प्रस्तुत किया। तीस जिलों का चयन किया गया, और निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए:**

- **श्रेणी I:** जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए 8 पुरस्कार।
- **श्रेणी II:** जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए 13 प्रमाणपत्र।
- **श्रेणी III:** जिला कौशल विकास योजना के लिए 9 प्रशंसा पत्र।

बाद में एक संवाद सत्र में, अधिकारियों ने माननीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, और माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के लिए से मुलाकात की और अपने क्षेत्र में किए गए सर्वोत्तम कार्यों को साझा किया।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने जिला कलेक्टरों, जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को कुशल कार्यबल की मांग-मैपिंग करने और स्थानीय स्तर पर कौशल विकास पहल के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्किलिंग एक आजीवन प्रक्रिया है और डीसी को कौशल विकास की निरंतरता को पूरी तरह आगे बढ़ाना चाहिए और जिला स्तर पर अभिनव योजना के माध्यम से कौशल विकास इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए।

प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न हुए हालिया व्यवधानों के आलोक में, जिलों को दोनों मंत्रियों से कौशल विकास की दिशा में एक बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी गई।

सूक्ष्म-कार्यान्वयन के लिए मैक्रो-प्लानिंग के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण से निर्देशित, डीएसडीपी पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास योजना के साथ जिला योजनाओं को एकीकृत करने में डीएससी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।

सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने कहा कि कौशल विकास की सभी योजनाओं को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए, और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर जिलों के निर्माण के माध्यम से है। **कौशल विकास और उद्यमशीलता, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर** ने कहा कि पुरस्कार एक सहायक कौशल इकोसिस्टम बनाने के केंद्र के इरादे को दर्शाते हैं जहां बहु-कौशल के अवसरों ने आजीविका की संभावना के लिए 'ग्राम इंजीनियरों' को जन्म दिया और वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि कौशल नियोजन के पीछे के विज्ञान और पद्धति का उद्देश्य कौशल और अनेक जाँब रोलों के कई मार्ग बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने का होना चाहिए।

श्री वेद मणि तिवारी, मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भी स्किल इंडिया डिजिटल कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें स्थानीय प्रशासन को स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भविष्य के कौशल और अवसरों पर प्रकाश डाला गया।

जिलों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए, श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कहा, "अपने अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर, भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने की

राह पर है। उमदराज आबादी वाले कई देश कुशल कामगारों के लिए भारत पर निर्भर हैं और वैश्विक कंपनियां भारत में कारोबार शुरू करने की इच्छुक हैं। देश के युवाओं को कौशल, कौशल और कौशल बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है और जिले इस मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं सभी जिलाधिकारियों को वैश्विक परिदृश्य पर नजर रखने और उसके अनुसार अपने कौशल विकास कार्यक्रमों को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।

उच्च मूल्य संवर्धन अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए, जिलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षित युवाओं को भी इस प्रक्रिया में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। मैं डीएसडीपी पुरस्कारों के सभी विजेताओं को बधाई देता हूँ और कार्यात्मक और अभिनव योजनाएं बनाने में उनके उत्कृष्ट प्रयास की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि जिला स्तर के संसाधनों और संस्थानों के अधिकतम उपयोग से हम स्किल इंडिया बनाने के सपने को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।

जीतने वाले जिलों में, राजकोट डीएससी ने जिले में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं को लागू किया है। दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को कुशल बनाने पर अधिक ध्यान देने के साथ, जिले ने सीखने में अक्षम और डिस्लेक्सिया वाले लोगों का समर्थन किया है।

लघु शेल्फ जीवन और उच्च परिवहन लागत असम के कछार जिले के अनानास किसानों के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला चुनौती पेश कर रही थी, जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में फलों का निपटान करने और उन्हें बाजार मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनानास के उत्पादन के लिए एक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करके स्थानीय स्तर पर उत्पाद, कछार डीएससी समस्या का समाधान करने के लिए एक त्वरित समाधान के साथ आया। इसने किसानों को एक बार फिर से अच्छे लाभ पर अनानास बेचने के लिए फ्लेक्स और सौदेबाजी की क्षमता प्रदान की।

महाराष्ट्र के सतारा में, डीएससी ने आपदा प्रबंधन के लिए कौशल को मजबूत करने और कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया। जिले के पास कौशल प्रशिक्षण के साथ कोविड के दौरान प्रभावित महिलाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी भी है।

कौशल विकास के क्षेत्र में जिलों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने, स्वीकार करने और पुरस्कृत करने के लिए जून 2018 में एमएसडीई द्वारा कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के लिए आजीविका संवर्धन (संकल्प) स्कीम के तहत डीएसडीपी पुरस्कार स्थापित किए गए थे। पहला डीएसडीपी पुरस्कार समारोह 2018-19 में आयोजित किया गया था, जिसमें 19 राज्यों के 228 जिलों ने भाग लिया था। नवाचार को बढ़ावा देने और कौशल विकास पहल के साथ स्थानीय आजीविका को सक्षम करने की योजना वाले जिलों को पुरस्कारों के लिए चुना गया था।

एमएसडीई ने यह परिकल्पना की है कि ये पुरस्कार सभी जिला कौशल समितियों (डीएससी) को प्रोत्साहित करेंगे और जिला स्तर पर लक्षित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्षमताओं का उपयोग करके डीएसडीपी के बारे में बेहतर समझ को बढ़ावा देंगे। परियोजना का उद्देश्य संकल्प की प्राथमिक पहल के प्रभाव को अधिकतम करना है, जो राज्य और जिला स्तर पर कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना है।

पुरस्कार प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिए आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर को मूल्यांकन भागीदार के रूप में चुना गया था।

### संकल्प के बारे में

कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के लिए आजीविका संवर्धन ("संकल्प") विश्व बैंक की ऋण सहायता से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य संस्थानों को मजबूत करने, बेहतर बाजार संपर्क बनाने और समाज के वंचित वर्गों को शामिल करने के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना है।

संकल्प के बारे में अधिक जानकारी [www.sankalp.msde.gov.in](http://www.sankalp.msde.gov.in) से प्राप्त करें।

### अनुलग्नक

विजेता जिलों का विवरण नीचे दिया गया है

रैंकिंग	राज्य	ज़िला
1	गुजरात	राजकोट
2	असम	कछार
3	महाराष्ट्र	सतारा
4	केरल	मलप्पुरम
5	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग
6	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग
7	बिहार	गया
8	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा
9	बिहार	अररिया
10	उत्तर प्रदेश	बहराइच
11	हिमाचल प्रदेश	मंडी
12	महाराष्ट्र	वाशिम
13	गुजरात	पाटन
14	उत्तराखंड	बागेश्वर



**Skill India**  
कौशल भारत - कुशल भारत



सत्यमेव जयते  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT  
& ENTREPRENEURSHIP

15	तमिलनाडु	तिरुपूर
16	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
17	उत्तर प्रदेश	चंदौली
18	महाराष्ट्र	थाइन
19	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
20	चंडीगढ़	चंडीगढ़
21	छत्तीसगढ़	महासमुंद
22	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
23	झारखंड	गिरिडीह
24	गुजरात	सुरेंद्रनगर
25	कर्नाटक	रायचुर
26	महाराष्ट्र	सोलापुर
27	केरल	त्रिशूर
28	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
29	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम
30	हरियाणा	नूह (मेवात)